

प्रभक,

संजीव कुमार शर्मा,
अनुसंधान,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,

राज्य परियोजना सलाहकार,
राज्य परियोजना सरलीकरण इकाई,
142 फ़ेस-1, बसन्त विहार,
देहरादून।

विशेषाज्ञा-8 (तकनीकी)

देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2007

विषय:-

विश्व बैंक सहायित परियोजना टीईक्यूआईपी के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु द्वितीय किस्त के रूप में डीआईटी देहरादून को धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपक पत्रांक-830/एसपीएफयू/बजट/2006-07 दिनांक 15.3.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विश्व बैंक सहायित परियोजना टीईक्यूआईपी के अन्तर्गत चयनित निजी क्षेत्र की संस्था-देहरादून इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून हेतु पूर्ण परियोजना अवधि के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत ऋण की धनराशि रु 59.84 लाख में से इस वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु रु 29.34 लाख (कमसे कम) राशि वित्तिय हजारे मात्र) की धनराशि ऋण के रूप में श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-

इस संबंध में शासनादेश संख्या-164/प्रा.शि./2004 दिनांक 17.5.2004 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अर्थात :-

- क- स्वीकृत किये जाने वाले ऋण की धनराशि पर भारत सरकार द्वारा 12.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से व्याज लिया जायेगा।
- ख- सम्पूर्ण ऋण की धनराशि के लिए प्रारम्भिक तीन वर्षों का मॉरिटोरियम प्रारम्भ होने के बाद ऋण के वापसी व्याज सहित 07 वार्षिक किस्तों में की जायेगी।
- ग- स्वीकृत ऋण की धनराशि का कम से कम 20 प्रतिशत अधिक बचक राज्य के पक्ष में रखे जाने हेतु बैंक गारण्टी बचक के रूप में 10 वर्ष की अवधि

अनुसंधान
(संजीव कुमार शर्मा)
आज्ञा से,

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. विल अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग।
4. निदेशक, जी.आई.टी. देहरादून।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गाई फाइल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

संख्या व दिनांक तदैव

अनुसंधान
(संजीव कुमार शर्मा)

भवदीय,

- 3- इस संबंध में होने वाला अन्य कार्य विलीय वर्ष 2006-07 के अनुदान
संख्या-11 के अधीन लेखाधीन-2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनागत-00-800-
अन्य व्यय-97-वाह्य सहायता परियोजना-9701-प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार
कार्यक्रम-30-निवेश/अण (जीआईटी देहरादून को अण) सहायक अनुदान
/अनुदान/राजसहायता के नाम से जाला जायेगा।
- 4- यह आदेश विल विभाग की अशासकीय संख्या-1862/विल
अनुभाग-3/2006 दिनांक 30.03.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उत्तरांचल के नाम से बैंक गारण्टी ली जाय।

बाल सहित अण की वापसी) संख्या से निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
हेतु 03 वर्ष का मैरिटोरियम पीरियड तथा उसके उपरान्त 07 वर्षों में